जो धर्म
यंत्रवत्
बनता है,
वह धर्म नहीं कहा
जा सकता है।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोक जीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 195 | जयपुर. शनिवार . | 14 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

चौथे चरण का चुनावी रण आज, 1.06 करोड़ मतदाता करेंगे फैसला

जयपुर (कासं)। राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों के चौथे फेज में शनिवार को 25 जिलों की जिला परिषद और 116 पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। 25 जिला परिषद के 382 वार्डों में 1322 और 116 पंचायत समितियों के 2142 वार्डों में 7521 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

1 करोड़ 5 लाख 94 हजार 285 वोटर इनकी हार-जीत का फैसला करेंगे। इनमें 54 लाख 88 हजार 275 पुरूष और 51 लाख 05 हजार 951 महिला वोटर हैं। चौथे फेज में 11,905 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चौथे फेज में जिला परिषद और पंचायत समितियों में कई नेताओं के बेटे, बेटियां, बहू और रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह और उनकी बहू चूरू से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों में श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 30 जिला परिषद वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा 101 प्रत्याशी हैं। पंचायत समिति मेंबर्स के मामले में भी श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 553 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 164 पंचायत समिति वार्डों में चुनाव हो रहे हैं।

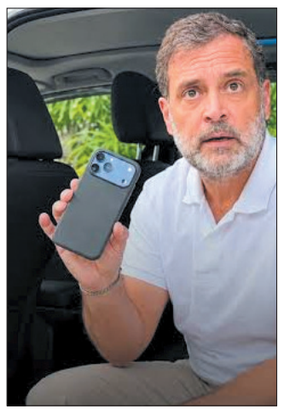
ऑनलाइन त्यौहारी बिक्री 17% बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। त्यौहारी सीजन में देश में ऑनलाइन बिक्री सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रूपये हो गई। डेटम इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नौ नवंबर तक त्यौहारी सीजन की अवधि 34 दिन रही है। पिछले साल त्योहारी सीजन 30 दिनों का था और तब आनलाइन त्योहारी बिक्री 1.2 लाख करोड़ रूपये रही थी। क्विक कामर्स प्लेटफार्म के जरिये आने वाले आर्डर में सालाना आधार पर 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ब्रांड वेबसाइटों पर 27-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्केटप्लेस के जरिए आने वाले आर्डर में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेल के पहले 21 दिनों में ऑनलाइन कार्ड ट्रांजेक्शन में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इनका कुल मूल्य छह प्रतिशत कम रहा। औसत कार्ड पेमेंट 2025 के 6,830 रूपये से 13 प्रतिशत घटकर 5,970 रूपये रह गया। प्रत्येक वर्ष की त्योहारी ई-कामर्स बिक्री में स्मार्टफोन की बड़ी हिस्सेदारी रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा। इस साल त्योहारी जीएमवी में मोबाइल फोन का योगदान लगभग 25 प्रतिशत रहा। 2025 में यह 35.2 प्रतिशत था। ऑनलाइन के जरिये स्मार्टफोन की बिक्री की संख्या में 25-35 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि औसत बिक्री मूल्य में 16-19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



राहुल का पीएम मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप, खुली बहस की चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए फोन टैपिंग का दावा किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि प्र.म. मोदी मेरा फोन टैप करा रहे हैं। इस आरोप के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी है।



भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आते हैं, इसका सबूत यहां है। मेरे इस फोन में है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं। जिस दिन वह आमने-सामने की बहस के लिए आएंगे, उस दिन सभी को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है, देशविरोधी कौन है और वह कब से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है। राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि इसके अलावा भी कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनके बारे में मुझे पता है और जो मेरे फोन में मौजूद हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्र.म. मोदी को राहुल गांधी की चुनौती देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए। अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए।

राहुल गांधी जी ने प्र.म. मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है! किसके इशारे पर कौन चलता है, कौन देशहित के खिलाफ काम कर रहा है और किसके पास क्या सबूत हैं, सब देश के सामने रखे जाएंगे.. मोदी जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए! अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए! वहीं, फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक

सूखाग्रस्त राजस्थान को 9,321 करोड़ का राहत पैकेज

15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, किसानों-पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने एवं आमजन, किसानों व पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आवश्यकतानुसार चारा डिपो का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए। साथ ही, गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल व चारे की समुचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीबी-जीराम-जी, राजीविका एवं आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाए। उन्होंने प्रभावित जिलों में खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आंकलन रिपोर्ट तैयार करने तथा काश्तकारों को राहत पहुंचाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं, विद्युत विभाग द्वारा नलकूप के विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएं। उन्होंने आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मानसून सत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत कम होने के कारण कुल 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन तहसीलों में से 73 तहसील गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी एवं 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित जन स्वास्थ्य एवं गौ-पालन, कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, वित्त, ई.जी.एस. व जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।



देशभर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश

जयपुर। आगामी दिसंबर माह में जयपुर में राजीविका के राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से देशभर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन में प्रदेश की समृद्ध कला से संबंधित स्थानीय उत्पादों को शामिल करने एवं प्रदेश की राजीविका महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैठकें आयोजित कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजीविका एवं डेयरी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि ये सेक्टर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें उत्पाद निर्माण के साथ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एवं बिक्री के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अब तक 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के बेहतर अवसरों के साथ उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध करवाना जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इससे उनके उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी और आय के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने सरस सखी योजना को ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा में अभिनव पहल बताया। उन्होंने कहा कि राजीविका एवं डेयरी विभाग संयुक्त कार्ययोजना को प्रभावी रूप से लागू करते हुए उत्पादों को एकीकृत विपणन नेटवर्क से जोड़े। साथ ही, उन्होंने सरस सखियों को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

भारत के पहले एलईडी डोम तारामंडल 'कॉसमॉस-मैसूरू' का मोदी ने किया उद्घाटन



मैसूर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मैसूर में 'कॉसमॉस-मैसूर तारामंडल' का उद्घाटन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा निर्मित, 'कॉसमॉस-मैसूरू' भारत का पहला एलईडी डोम तारामंडल है। खगोल विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिकल्पित यह तारामंडल, चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में मैसूरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। तारामंडल के 'स्काई थियेटर' में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने लद्दाख के हानले में तैनात 'एस्ट्रो-एम्बेसडर्स' (खगोल-दूतों) के साथ वर्चुअल बातचीत की। इस अत्याधुनिक सुविधा में 15 मीटर का झुका हुआ डोम है, जिसमें लगभग 6,150 पैनल लगे हैं और इनमें कुल 4.2 करोड़ एलईडी हैं। पारंपरिक तारामंडलों के विपरीत, जहां एक साधारण डोम पर तस्वीरें दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। यहां लगे एलईडी पैनलों को रियल-टाइम में नियंत्रित किया जा सकता है। शानदार विजुअल अनुभव मिलता है। खगोल विज्ञान की शिक्षा के लिए नई संभावनाएं खुलती हैं। 'स्काई थियेटर' में पेशेवर रूप से तैयार किए गए खगोल विज्ञान कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। यहां एक ऐसी फिल्म भी दिखाई जाएगी जो मैसूरू के इतिहास और खगोल विज्ञान के बीच के संबंध को दर्शाती है। ये शो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'कुछ महीने पहले ही, मैं 'विवेक स्मारक' के उद्घाटन के अवसर पर आप लोगों के बीच था, और आज हम यहां 'कॉसमॉस तारामंडल' को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये दोनों ही अवसर भारत की संस्कृति और मूल्यों के बारे में एक गहरा संदेश देते हैं। 'विवेक स्मारक' हमें अपने भीतर झांकने और आध्यात्मिक ज्ञान खोजने की प्रेरणा देता है, जबकि 'कॉसमॉस तारामंडल' हमारा ध्यान आकाश की ओर ले जाता है, और हमें इस विशाल ब्रह्मांड को जानने और इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रेरित करता है।

भीषण सड़क हादसा, 24 की मौत, 20 घायल

काजीरंगा (एजेंसी)। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक, हादसे में 20 लोग घायल हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा कोहोरा रेंज में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर हुआ। यह घटना हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन इलाके में हुई। यहां यात्रियों से भरी मिनी बस की कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई। गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल डेका ने बताया, हमें शुरूआती जानकारी मिली है कि हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है। हम सभी मौके पर मौजूद हैं। बस से शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी सही जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि, शुरूआती रिपोर्ट के मुताबिक बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को कोहोरा मॉडल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल ज्यादातर लोगों को बोकोखात और गोलाघाट के अस्पतालों में भेजा गया। कुछ घायलों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी रेफर किया गया। अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में दो महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कई कॉलेज के छात्र थे। हादसे के समय वे अपनी कक्षाएं खत्म करके लौट रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, बस बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। वह पार्क के पास लगाए गए गति संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी। हमें शक है कि मिनी बस के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस कंटेनर ट्रक से टकरा गई।



ऑपरेशन सिंदूर में 427 जिलों का सुरक्षा नेटवर्क सक्रिय, भविष्य के युद्ध की तैयारी का खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के 427 जिलों में नागरिक सुरक्षा नेटवर्कको सक्रिय किया गया था। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की बढ़ती भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर ही तय नहीं होंगे बल्कि बिजली संयंत्रों, औद्योगिक संस्थाओं, खदानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के द्वार पर भी होंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और नागरिक सुरक्षा नेटवर्क देश को भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, इस देश की सुरक्षा सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं, बल्कि सुबह तीन बजे एक बिजली संयंत्र के गेट पर भी तय होती है।



ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आप अगले युद्ध में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मदद के लिए 7 मई को देश भर के लगभग 427 जिलों को सक्रिय किया गया था। उन्होंने कहा कि सक्रियता व्यापक तैयारियों का हिस्सा थी। इससे भारत को रणनीतिक रूप से मदद मिली। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता किसी एक हथियार या प्रणाली का परिणाम नहीं थी, बल्कि कई परतों के एक साथ काम करने का परिणाम थी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन को रोकने वाला कोई एक हथियार नहीं था। यह परतें थीं, एक संगठन के सेंसर, दूसरे के जैमर और तीसरे की बंदूकें, सभी एक फ्रेम में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत को भारत की आंतरिक सुरक्षा वास्तुकला का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसमें निजी सुरक्षा कर्मी पहचान की पहली परत के रूप में काम करते हैं। निजी सुरक्षा कर्मियों को देश का सबसे बड़ा संभावित मानव सेंसर नेटवर्क बताते हुए उन्होंने उन्हें देश का पहला सेंसर कहा जो संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और जमीन से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। भारत में नागरिक सुरक्षा नेटवर्क एक स्वयंसेवी और समुदाय-आधारित व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य युद्ध, बाहरी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान नागरिकों की रक्षा करना, जान-माल के नुकसान को कम करना और देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना है।

योगनिद्रा से जागेंगे विष्णु, 27 दिनों में शादी के 12 मुहूर्त

- देवउठनी एकादशी से शुरू होंगे मांगलिक कार्य, 21 नवंबर से 12 दिसंबर तक विवाह की लग्न

वाराणसी (एजेंसी)। चातुर्मास के चार माह बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी पर 20 नवंबर को भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागृत होंगे। इसी के साथ विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरूआत हो जाएगी। बैंडबाजे और शहनाई की मंगल धुन गूंजने लगेगी। 16 दिसंबर को खरमास शुरू होने से पहले विवाह के 12 मुहूर्त बन रहे हैं। विवाह के लग्न 21 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक रहेंगे। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि के पालन, पोषण और संरक्षण का कार्य पुन: संभालते हैं। इसके साथ ही विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।



आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री के अनुसार, सूर्यदेव 15 दिसंबर को दिन में एक बजे मूल नक्षत्र में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। सूर्य के 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति के बाद मांगलिक कार्य दोबारा शुरू होंगे।

विष्णु और तुलसी का विवाह संपन्न होगा

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रख्यात ज्योतिषविद प्रो. नागेंद्र पांडेय ने बताया कि देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को भोर में 3:30 बजे शुरू होकर रात 1:54 बजे तक रहेगी। इसी दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को शुक्र पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं। सूर्यदेव 18 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में सूर्य तुला राशि में हैं। 20 नवंबर को भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही मांगलिक कार्यों के योग बनने लगेंगे।

नवंबर में 5 और दिसंबर में 7 विवाह मुहूर्त

- नवंबर में 21, 24, 25, 26 और 30 तारीख को विवाह के मुहूर्त हैं। वहीं, दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 तारीख को विवाह का लग्न रहेगा।

- इसके बाद नए साल में मकर संक्रांति के बाद 18 जनवरी से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। फरवरी में विवाह के अधिक मुहूर्त बन रहे हैं।

- वहीं, 15 मार्च 2027 से एक बार फिर मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी जिंदोरी

उच्च शिक्षा की बदहाली और एआई का बढ़ता खतरा

आज हमारे ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थानों की हालत स्कूली शिक्षा से भी बदतर है और उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। नियोक्ता लगातार हमारी स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता की बुराई करते हैं, फिर भी लोगों की सोच, नीति-निर्माण और नागरिक समाज की गतिविधियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। आखिर यह स्थिति क्यों है? ये सिर्फ भारत के लिए नहीं हैं और यह कोई संपूर्ण सूची भी नहीं है। सबसे पहली वजह, स्कूलों के बजाय कॉलेजों के पाठ्यक्रम को तय करना ज्यादा मुश्किल है। हमें इस बात पर विचार करना ही होगा कि क्या उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी के लिए तैयार करना है? अगर है भी, तो किस प्रकार की नौकरी के लिए? या फिर छात्रों को जागरूक नागरिक और आलोचनात्मक विचारक भी बनाना है? क्या उच्च शिक्षा यह दोनों काम नहीं कर सकती? ये कोई मामूली सवाल नहीं हैं, लेकिन हमारे संस्थानों ने शायद ही कभी ईमानदारी से इनका जवाब देने की कोशिश की हो। उच्च शिक्षण संस्थानों ने शिक्षण को अनुसंधान के साथ मिला दिया है और इसे ही सर्वमान्य सत्य के रूप में मान लिया। बहुत कम शिक्षण संस्थान या शिक्षक, दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आम तौर पर ज्यादातर अनुसंधान बहुत घटिया किस्म के होते हैं। कुछ जो ठीक-ठाक होते भी हैं, तो उसका छोटा सा हिस्सा ही अच्छा होता है। यह संस्कृति इसलिए चल रही है, क्योंकि इससे शिक्षकों को एक पहचान मिलती है और इससे भी अधिक, उनके काम का बोझ हल्का होता है। दोनों को एक साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। बौद्धिक रूप से सक्रिय रहना और वैसा अनुसंधान करना, जिसे हमारी प्रणाली या वैश्विक प्रणाली सराहती है- अलग-अलग बातें हैं। दोनों में घालमेल दरअसल उच्च शिक्षा के बारे में हमारी सोच में कमी को ही उजागर करती है।

शिक्षकों और छात्रों के बीच एक अलिखित समझौता सा हो गया है कि न आप कक्षाओं को गंभीरता से लेंगे, न हम इनको जरूरी मानेंगे। कई संस्थानों में हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि उनमें छात्र कक्षाओं में नहीं आते और शिक्षक भी इससे खुशी महसूस करते हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विभागों पर करीबी नजर रखने वाला हर व्यक्ति ऐसे संस्थानों के बारे में जानता है। इस दुरभिसंधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है कि कोई पढ़े और कोई पढ़ाए। उच्च शिक्षण संस्थान बदलाव-विरोधी हैं, वे इसके प्रतिरोध में माहिर हैं। उनका मुख्य काम जनमत तैयार करना और उसे दिशा देना है, इसलिए किसी भी सुधार को वे फौरन 'अच्छाई बनाम बुराई' की जंग बना देते हैं या उसे आजादी पर हमला, या अच्छाई पर प्रहार का रूप दे देते हैं। संस्थान के भीतर के लोग जानते हैं कि इन बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। उच्च शिक्षा के लिए सरकारों से धन देने में कमी की जा रही है। इसका नतीजा है, शिक्षा का घातक व्यवसायीकरण। इसके साथ ही तंत्र ने इसमें बाहरी दखल और भ्रष्टाचार के लिए दरवाजा खोल दिया है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' में इन मामलों को कैसे सुलझाया गया है। यहां खतरा इससे भी बड़ा है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का। इससे शिक्षा खोखली हो रही है, क्योंकि इसमें शिक्षक मशीन से पाठ तैयार करने लगा है, छात्र मशीन से जवाब तैयार करता है और एक अन्य मशीन उसके लिखे हुए का मूल्यांकन करने लगी है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव दिमाग का कहीं कोई उपयोग नहीं है। सोचिए, यह कितनी भयावह स्थिति है और दूसरी ओर इन सबसे बेपरवाह नेता, अकादमिक, प्रशासक अधिक से अधिक एआई के उपयोग की मांग कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में जो एक अहम बात है, वह हमारी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अच्छे संस्थान और बेहतरीन शिक्षक हैं। हालांकि, इनमें से केवल 10-15 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान ही अपने काम को लेकर गंभीर हैं और शायद 20-25 प्रतिशत शिक्षक ही प्रतिबद्ध और मेहनती हैं। ऊपर जिन कमियों की चर्चा की गई हैं, वे सब इन पर लागू नहीं होती हैं। इन मुश्किलों के बावजूद वे बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पूरे शिक्षा तंत्र का ज्यादातर हिस्सा बेकार हो चला है, जिस पर हमारा बहुत कम ध्यान जा रहा है। अगर हम इन गड़बड़ियों को नहीं देख पाते हैं और उसे जारी रखते हैं, तो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एआई का दानव जानलेवा हो सकता है।

जो लोग अपने सिर को रेत में छिपाए शुतुरमुर्ग की तरह 'तकनीक को हमेशा अच्छी चीज' मानने वाली सोच से प्रेरित हैं, उन्हें अपना सिर अब रेत से बाहर निकालकर दुनिया को साफ नजरों से देखना चाहिए। इससे जो समझ बनेगी, उसमें अधिकतर शिक्षण तंत्र से एआई को हटा दिया जाएगा और एक अच्छे उच्च शिक्षण तंत्र की नींव रखने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी, जो पुरानी सोच से बंधा हुआ न हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमेशा की तरह इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके पास आज बहुत कम है और जिन्हें अच्छी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।

प्रदेश के स्कूलों में जल्द लागू होगा नया स्टाफिंग पैटर्न, शिक्षकों का होगा समानीकरण

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश, 250 करोड़ से 1,941 मरम्मत कार्य शुरू; 300 जर्जर स्कूलों की जगह बनेंगे नए भवन

जयपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, नवीन स्टाफिंग पैटर्न से अध्यापको का समानीकरण लागू करने तथा वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठकें आयोजित हुईं। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नवीन स्टाफिंग पैटर्न की वर्तमान स्थिति तथा इन्हें लागू करने से संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। दिलावर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर नवीन स्टाफिंग पैटर्न को जल्द लागू करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, भवन निर्माण एवं मरम्मत, विद्यार्थियों को सहायता, व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा तथा तकनीक आधारित शिक्षण से संबंधित 15 बिंदुओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विद्यालय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा—

विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपये के 1,941 कार्यों की वित्तीय सहमति प्राप्त हुई है। इनमें से 1,934 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी प्रकार, 300 जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण के लिए 409 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 147 कार्यों के कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं।

आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार—

प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज विद्युत कनेक्शन, वाशिंग मशीन तथा ऑटोमेटिक रोटी मेकर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणा की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रथम चरण में 54 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 116.18 लाख रुपये की वित्तीय सहमति प्राप्त हुई है तथा सात विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। वाशिंग मशीन एवं ऑटोमेटिक रोटी मेकर की खरीद के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के हित में महत्वपूर्ण पहल—

कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार 'निपुण कैलेंडर' की छपाई पूर्ण होने तथा वितरण की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई। वहीं, कक्षा नौ में प्रवेश लेने वाली एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को ई-वाउचर के स्थान पर खुली निविदा के माध्यम से



साइकिल खरीदकर वितरित करने के लिए वित्तीय सहमति प्राप्त हो चुकी है। बैठक में चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट अथवा लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ई-वाउचर के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।

व्यावसायिक एवं समावेशी शिक्षा को मिलेगा प्रोत्साहन—

बैठक में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तथा आवश्यक उपकरणों एवं संचालन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी गई। 'स्कूल टू वर्क' कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालयों पर 41 विद्यालयों को चिह्नित करने की प्रक्रिया तथा 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने के प्रस्ताव की स्थिति भी प्रस्तुत की गई। इन 500 विद्यालयों में 100 विद्यालय ग्रीन एनर्जी तथा 400 विद्यालय अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए चिह्नित किए गए हैं।

एआई आधारित शिक्षण एवं सीएम-राइज विद्यालयों की तैयारी—

एक हजार विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा के तहत प्रथम चरण में 500 विद्यालयों का चयन पूर्ण कर लिया गया है। वहीं, सीएम-राइज योजना के अंतर्गत 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 10,848 शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राप्त 11.34 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के परीक्षण की प्रगति से भी अवगत करवाया गया।

प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर—

विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री एवं 'जादुई पिटारा' उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव की समीक्षा की गई। जयपुर एवं कोटा में चयनित विद्यालयों तथा उनसे सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने के लिए प्रस्तावित पायलट की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इसी प्रकार, प्रदेश के लगभग 75 हजार विद्यार्थियों की नेत्र जांच करवाने एवं आवश्यकतानुसार चश्मे उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा के संबंध में नोडल अधिकारियों के नामांकन तथा प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दिशा-निर्देश जारी किए जाने की जानकारी दी गई। इस कार्य को चिकित्सा विभाग को हस्तांतरित करने की सहमति के लिए पत्रावली भी भेजी गई है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जाए। उन्होंने नवीन स्टाफिंग पैटर्न एवं समानीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के साथ ही विद्यार्थियों के हित से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती रश्मि शर्मा, संयुक्त सचिव महेन्द्र खींची, संयुक्त सचिव दिव्यांशु सिंह, उप शासन सचिव श्रीमती मुन्नी मीना,अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक अशोक कुमार मीना सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सत्ता पर अंकुश का लोकतांत्रिक हथियार हैं मध्यावधि चुनाव

हाल के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भी इसी तरह की ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। उन्होंने सीनेट की कम से कम सात और प्रतिनिधि सभा की 40 सीटें अपने पक्ष में कर ली हैं। अमरीकी जनता ट्रंप की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली, दिखावे वाली घमंडी परियोजनाओं, और अपने परिवार के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पद के इस्तेमाल से परेशान हो चुकी थी। उनकी नीतियों, विशेषकर आयात शुल्क और ईरान के साथ युद्ध ने महंगाई को और बढ़ा दिया। वहीं, अवैध प्रवासियों के खिलाफ बल प्रयोग ने जनता की नैतिक संवेदनाओं और उदारवादी मूल्यों को आहत किया। चुनावों से ठीक पहले उनकी लोकप्रियता घटकर महज 38 प्रतिशत रह गई थी।

अमरीकी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी की हार कोई असामान्य घटना नहीं है। वर्ष 1946 से 2022 के बीच हुए 20 मध्यावधि चुनावों में से 18 में व्हाइट हाउस में सत्तारूढ़ पार्टी को प्रतिनिधि सभा में अपनी सीटें गंवानी पड़ीं। इन चुनावों में औसतन 26 सीटों का नुकसान हुआ। लगभग हर बार ऐसी हार राष्ट्रपति को अपनी नीतियों और राजनीतिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। वर्ष 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 54 सीटें गंवा दीं और 40 वर्षों में पहली बार कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद क्लिंटन ने अपनी नीतियों में उल्लेखनीय बदलाव किया। उन्होंने अधिक सरकारी खर्च की मांग करने वाले उदारवादियों और छोटी सरकार की वकालत करने वाले रूढ़िवादियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी, 'बड़ी सरकार का दौर समाप्त हो चुका है।'

वर्ष 2006 में इराक युद्ध को लेकर जनता की बढ़ती नाराजगी के कारण जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण खो दिया। बुश को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने नेतृत्व में तत्काल बदलाव करना पड़ा। उन्होंने विवादास्पद रक्षा मंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड को पद से हटा दिया और अपनी विदेश नीति टीम में फेरबदल किया।

बराक ओबामा ने वर्ष 2010 के मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा की 63 सीटें गंवाने को अपनी पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक पराजय बताया था। इस हार ने उन्हें व्यापक विधायी सुधारों की अपनी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इनमें अफोर्डेबल केयर एक्ट जैसी पहल भी शामिल थी। ट्रंप इस राजनीतिक वास्तविकता का अनुभव पहले भी कर चुके हैं। वर्ष 2018 में जब रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 41 सीटें गंवाईं, तो उनकी विधायी महत्वाकांक्षाओं पर अचानक विराम लग गया। विपक्ष ने आगे के विधायी बदलावों को रोक दिया और इसके बजाय उनके प्रशासन के खिलाफ जांच की एक श्रृंखला शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें दो बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। मध्यावधि चुनाव अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में सत्तावाद के खिलाफ शायद सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच हैं। ये चुनाव मतदाताओं को राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में ही वाशिंगटन में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदलने का अवसर देते हैं। एक अलग कांग्रेस (संसद) का चुनाव करके अमरीकी जनता राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकती है। यह व्यवस्था इसलिए कारगर है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास स्वयं कानून बनाने का अधिकार नहीं होता और कार्यकारी शक्तियों पर संविधान की ओर से कई महत्वपूर्ण सीमाएं लगाई गई हैं। कानून केवल कांग्रेस बना सकती है। सरकारी खर्च को मंजूरी देने और संघीय न्यायपालिका सहित सरकार के वरिष्ठ पदों पर राष्ट्रपति की नियुक्तियों को स्वीकृति देने का अधिकार भी कांग्रेस के पास ही है। विपक्ष के नियंत्रण वाली कांग्रेस राष्ट्रपति के साथ सहयोग करने से इनकार कर सकती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह संदिग्ध फैसलों की जांच कर सकती है, सत्ता के दुरुपयोग को उजागर कर सकती है, सरकारी धन के आवंटन पर रोक लगा सकती है, विधेयकों को खारिज कर सकती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने तथा उन्हें पद से हटाने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति न तो कांग्रेस को भंग कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है। अमरीका के संस्थापक नेताओं ने अनियंत्रित राजनीतिक शक्ति के खतरों को समझा था। उनका मानना था कि 'जहां वार्षिक चुनाव समाप्त होते हैं, वहीं अत्याचार की शुरुआत होती है।' इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें कांग्रेस के चुनाव हर दो साल में होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में मतदाताओं को अपनी पसंद जाहिर करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक चुनाव में मतदाता प्रतिनिधि सभा के सभी 435 सदस्यों और सीनेट के लगभग एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के बावजूद कांग्रेस की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है।

वास्तव में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज और देश की दिशा पर एक तरह का जनमत संग्रह हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सांसद, और नियमित मध्यावधि चुनाव, इन तीनों का मेल गलत नीतियों तथा सत्तावाद के खिलाफ एक मजबूत संस्थागत सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था के आलोचकों का तर्क है कि सरकार के विभाजित नियंत्रण से राजनीतिक गतिरोध पैदा होता है और सरकार के लिए तत्काल राष्ट्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना मुश्किल हो जाता है।

परंतु अमरीकी संविधान की रूपरेखा जानबूझकर इस तरह तैयार की गई है कि प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने की तुलना में तानाशाही को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जाए। मैं लंबे समय से यह तर्क देता रहा हूं कि अमरीकी शैली की राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने से भारत की जनता को अधिक लाभ होगा। भारत की मौजूदा संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण है, और चुनावों के बीच का अंतराल भी बहुत लंबा है। मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। 'आप हमारे संविधान की अन्य कोई भी व्यवस्था अपना सकते हैं, लेकिन मध्यावधि चुनावों के प्रावधान को अपने संविधान में शामिल मत कीजिए।' वर्ष 1947 में अमरीकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने भारत के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को यह सलाह दी थी। ऐसा लगता है कि राव ने ट्रूमैन की इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। वह केवल शिष्टाचार भेंट के लिए व्हाइट हाउस गए थे। अमरीका रवाना होने से पहले ही वह भारत की संविधान सभा को संविधान का प्रारूप सौंप चुके थे।

मेहनत, लगन और समर्पण को मिला सम्मान, 6 पुलिसकर्मी बने ''कॉन्स्टेबल ऑफ द मंथ''

जयपुर। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने शुक्रवार को पुलिस आयुक्तालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट, सराहनीय, मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को ''कॉन्स्टेबल ऑफ द मंथ'' अवॉर्ड से सम्मानित किया।

पुलिस आयुक्त मित्तल ने कहा कि जयपुर पुलिस का ध्येय 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' की भावना को साकार करना है। इसी उद्देश्य से पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देकर सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा वे और अधिक लगन, मेहनत एवं समर्पण के साथ जनसेवा के लिए प्रेरित होंगे।

अक्टूबर माह 2026 के ''कॉन्स्टेबल ऑफ द मंथ'' पुरस्कार के लिए जिला पूर्व से चिन्हित मनोज कुमार कानि. पुलिस थाना जवाहर सर्किल ने मुकदमा नम्बर 509ञ26 में सीसीटीवी फुटेज देखकर मुल्जिम विक्रम मीणा को तथा मुकदमा नम्बर 529ञ26 में लूट की वारदात करने वाले मुल्जिम तन्मय कुमार पारीक व विवेक सैन को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिला पश्चिम के सतवीर कानि. पुलिस थाना सिन्धी कैम्प ने थाना क्षेत्र में मोबाईल चोरी, स्नैचिंग करने वाली गैंग के सरगना मोईन उर्फ शाहरूख, मोहम्मद अनस,



मोहम्मद गालिब, हसीब मेव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी व स्नैचिंग के 20 मोबाईल एवं वारदात में उपयोग में ली गयी स्वीफ्ट डिजायर कार को बरामद करवाने में विशेष भूमिका रही। जिला उत्तर के विजय कुमार कानि. पुलिस थाना नाहरगढ़ ने मुकदमा नम्बर 221ञ26 में परिवादी के बैग में रखे हुये कुल 20 लाख रूपये में से 18 लाख 93 हजार रूपये बरामद कर वारदात को अंजाम देने वाले तीनों मुल्जिमों को गिरफ्तार करवाने एवं अन्य चोरी के प्रकरण में मुल्जिम को गिरफ्तार करवाने तथा चोरी के वाहन के चैचिस नम्बर व इंजन नम्बर मिटाकर कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी को भी गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। कानि. ने परिवादिया की नाबालिग बच्ची को दस्तयाब करवाने में अपनी कार्यकुशलता, लगन, निष्ठा का भी परिचय दिया।

जिला दक्षिण के रामवतार कानि. पुलिस थाना सांगानेर सदर ने महिला के ब्लाईन्ड मर्डर की वारदात का खुलासा करवाने तथा लूट के मामले में फरार चल रहे चार ईनामी अपराधियों को गिरफ्तार करवाने एवं एक अन्य प्रकरण में सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर 2 करोड़ के जीएस उपकरण के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया। राजेश कुमार कानि. यातायात उत्तर ने वनस्थली मार्ग चैराहा पर रेड लाईट पर रूके ऑटो में बैठी सवारी से मोटरसाईकिल पर सवार दो बदमाशों द्वार एक लाख रूपये से भरा बैग छीनने की वारदात पर अपनी मुश्तैदी से दोनों को पकड़कर रूपयों का बैग संबंधित को देकर, बदमाशों का मय मोटरसाईकिल के जालूपुरा थाना पुलिस को सुपूर्द किया।

दिनेश कुमार कानि. कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, लाईसेसिंग एवं लीगल, आयुक्तालय जयपुर ने पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय हेतु जारी किये गये अस्थाई अनुज्ञापत्रों से संबंधित कार्य का संपादन कड़ी मेहनत, लगन, ईमानदारी से किया है।

कार्यक्रम में ओमप्रकाश, विशेष पुलिस आयुक्त, डॉ. अजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), प्रदीप मोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन), डॉ. रामेश्वर सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम), योगेश गोयल, पुलिस उपायुक्त (क्राइम), श्रीमती अनुष्ठा कालिया, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) उपस्थित रहे।

नशा तस्कर की 32 लाख की संपत्ति फ्रीज

जयपुर। मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर तरुण नाहरिया एवं उसके परिजनों के नाम पर खरीदे गए चार वाहनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत फ्रीज करवाया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं सप्लाई से अर्जित अवैध आय से अपने नाम के साथ-साथ पत्नी और माता के नाम पर भी वाहन खरीदे थे।

सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली ने इन वाहनों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत 32 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत चालानशुदा अपराधियों के विरुद्ध उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ तथा वृत्ताधिकारी दक्षिण नगर मनीष बडगूजर के निकटतम सुपरविजन एवं मार्गदर्शन में रामगंज थानाधिकारी हरिपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

सक्षम प्राधिकारी ने जारी किए फ्रीजिंग आदेश- पुलिस टीम ने तस्करी से अर्जित अवैध आय से खरीदे गए वाहनों से संबंधित दस्तावेज जुटाकर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली के समक्ष धारा 68एफ(2) एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली ने दिनांक 9 नवंबर 2026 के आदेश के माध्यम से संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए। फ्रीज किए गए चार वाहनों में तरुण नाहरिया के नाम पर होंडा एनएक्स 200 मोटरसाइकिल, टोयोटा इनोवा 2.5V कार, पत्नी नेहा के नाम पर टीवीएस जुपिटर 125 मोटरसाइकिल और माता दुर्गा देवी के नाम पर एक टीवीएस वाहन शामिल है।

फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत 32 लाख रुपए आंकी गई है। घटना के अनुसार 6 अगस्त 2026 को थाना रामगंज पुलिस ने तरुण नाहरिया पुत्र सम्पत उम्र 31 वर्ष निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर को 31.46 ग्राम एमडी मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय और उससे खरीदी गई संपत्तियों की जांच शुरू की। वित्तीय अनुसंधान में आरोपी के नाम पर दो वाहन, उसकी पत्नी नेहा के नाम पर एक वाहन तथा उसकी माता दुर्गा देवी के नाम पर एक वाहन खरीदा जाना सामने आया।

ऑनलाइन मैरिज



ऑनलाइन के बढ़ते क्रेज ने सिर्फ पढ़ाई और जॉब को ही आसान नहीं बनाया है, बल्कि इसने लाइफ को भी बहुत ही आसान बना दिया है। फर्नीचर, कपड़ों से लेकर बाकी के घरेलू सामान को खरीदने के साथ ही अब जोडियां भी ऑनलाइन ही बनने लगी हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये कामयाब भी हो रही हैं। मनमुताबिक पार्टनर मिलने से शादियां लंबे समय तक बरकरार भी रह रही हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस सक्सेस के पीछे के कारणों के बारे में जानेंगे।

लड़ाइयां कम होती हैं



आपसी समझ



अरेंज मैरिज और लव मैरिज में भले ही बाद आपसी समझ में थोड़ी कमी हो जाए, लेकिन ऑनलाइन मैरिज में इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दरअसल, ऑनलाइन में हम अपने ड्रीम पार्टनर के बारे में भी बता सकते हैं और काफी हद तक वैसा ही पार्टनर ढूंढने में कामयाब भी हो जाते हैं। आपसी समझ बने रहने की सबसे खास वजह यही है।

ऑनलाइन मैरिज के वक्त ही ज्यादातर कपल्स अपने आगे की लाइफ की प्लानिंग कर लेते हैं और साथ ही जिम्मेदारियों का बंटवारा भी।

ऑनलाइन मैरिज में पुरुष हो या महिला, दोनों ही अपने मनमुताबिक पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन्स मौजूद हैं, जिनमें वो पार्टनर के संबंध में अपनी पसंद का ब्योरा दे सकते हैं। कद-काठी से लेकर, एजुकेशन, गोत्र, कम्युनिटी, फैमिली बैकग्राउंड आदि के बारे में जानकारियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक पार्टनर की तलाश आसान हो जाती है। यहां तक कि खाने-पीने की आदतों में भी अपनी पसंद को खुलकर ऑनलाइन पर बताया जा सकता है। ऑनलाइन मैरिज के वक्त ही ज्यादातर कपल्स अपने आगे की लाइफ की प्लानिंग कर लेते हैं और साथ ही जिम्मेदारियों का बंटवारा भी। वर्किंग वुमन होने पर घर के कौन-कौन से काम करने होंगे और किन कामों की जिम्मेदारियां पुरुषों के हवाले होंगी, ये पहले ही तय हो जाती हैं, जो अरेंज मैरिज में कम ही देखी जाती हैं। अरेंज मैरिज ज्यादातर पुरुष प्रधान होता है।

गर्लफ्रेंड को मनाना

रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने की बात हो या किसी महिला को इंप्रेस करने की, दोनों ही बहुत मुश्किल काम होते हैं। किसी रिलेशनशिप में होने पर पार्टनर की आदतों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे मनाना आसान होता है, लेकिन इंप्रेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। महिलाएं छोटी-छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढ लेती हैं। इसके लिए पुरुषों को साइकोलॉजी की किताब पढने की जरूरत नहीं। बस इन छोटी खुशियों का ख्याल रखकर रिश्ते में अपनापन और प्यार बरकरार रखा जा सकता है। जानते हैं इन ईजी स्टेप्स को.... एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो उसे शो करें। महिलाओं को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ आय लव यू कह देना ही काफी नहीं, उसके पीछे की फीलिंग को भी बताएं। हालांकि, पुरुष इस मामले में बहुत ही शर्मीले होते हैं। उन्हें न तो प्यार जताना आता है और न ही इसका तरीका पता होता है। लेकिन इंप्रेस करना है तो इस नेचर को बदलना होगा। गर्लफ्रेंड को अहसास कराएं कि वो कितनी स्पेशल है आपकी लाइफ में।





प्लानिंग के बारे में पूछें

प्यूचर प्लानिंग को लेकर भी सवाल पूछना सही रहता है और अच्छा माना जाता है। ज्यादातर मामलों में शादी के बाद महिलाओं को मजबूरी के कारण अपनी जॉब छोडनी पड़ती है, जो उनके लिए काफी मुश्किल होता है। अच्छी एजुकेशन के बाद जॉब छोडना उन्हें ज्यादा परेशान कर देता है। इसलिए महिला से इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार शादी के प्रेशर के में वो इसके लिए हामी तो भर देती हैं, लेकिन बाद में इसे लेकर पारिवारिक झगड़े और मन-मुटाव शुरूहोने लगते हैं।

महिलाओं को भी पुरुषों से उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सवाल पूछने चाहिए। इससे उनके इंटेलेक्चुअल होने के साथ ही उनकी समझ-बूझ और मैच्योरिटी को जानने का पूरा मौका मिलता है। पुरुष ज्यादातर अपनी ड्रीम गर्ल की चाहत में कई बार महिलाओं से अजीबोगरीब सवाल-जवाब करने लग जाते हैं। उनकी हेल्थ और उनकी डाइट पर फोकस करके उन्हें शर्मिंदा भी करने लगते हैं।

पहली मुलाकात की घबराहट

शादी जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। इसके लिए काफी सूझ-बूझ की जरूरत होती है। शादी की बात चलने से लेकर उसके फिक्स होने तक का एक-एक लम्हा बड़ा ही मुश्किल होता है। इससे पुरुष हो या महिला, दोनों को ही गुजरना पड़ता है। फैमिली से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई इसी कोशिश में लगा रहता है कि जरा-सी चूक बनी हुई बात को बिगाड़ सकती है। ऐसा देखा भी गया है। इसी के मद्देनजर शादी से पहले पुरुष और महिला की मुलाकात का सिलसिला शुरूहुआ ताकि वे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंधित सभी मामलों पर खुलकर डिस्कशन कर लें और फिर कोई फैसला लें। लेकिन इस मुलाकात के दौरान पुरुष और महिला दोनों ही इतने नर्वस होते हैं कि कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो शर्मिंदगी के साथ ही फनी भी होते हैं। तो इस पहली मुलाकात के दौरान क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। पहली मुलाकात के दौरान पुरुषों को महिलाओं से और महिलाओं को भी पुरुषों से उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि इस संबंध में खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार परिवार वाले दिखावे के चक्कर में एजुकेशन को लेकर झूठ बोल देते हैं, जिसे आपसी बातचीत से क्लियर किया जा सकता है।



मुंह की बदबू से परेशान हैं तो... इस तरह पा सकते हैं छुटकारा



कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके मुंह से अक्सर बदबू आती रहती है। ऐसे लोग किसी के भी सामने खुलकर बात करने से घबराते हैं। अगर आपका नाम भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शुमार है तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ बेहद आसान उपायों के जरिए अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में-

सौंफ का स्वाद



मुंह को फ्रेश रखने के लिए सौंफ से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका स्वाद तो बेहतरीन होता है ही, साथ ही इसके एंटी माइक्रोबियल तत्व बैक्टिरिया से लड़ने का भी काम करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप खाना खाने के बाद एक चम्मच सौंफ चबाकर खाएं। इसके अलावा आप चाहें तो सौंफ के पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ उबालिए और हल्का गुनगुना होने पर इससे कुल्ला करें।

रखें खुद को हाइड्रेट

गर्मी के मौसम में पानी की अधिकता सिर्फ निर्जलीकरण से ही आपको नहीं बचाती, बल्कि यह मुंह की दुर्गंध को दूर करने का भी एक आसान उपाय है। दरअसल, मुंह से बदबू आने का एक कारण आपके शरीर में पानी की कमी भी होता है। जब आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो इससे आपका मुंह सूखने लगता है और आपके मुंह में लार नहीं बनती। यही लार आपके मुंह के बैड बैक्टीरिया को नियंत्रित करती है और आपके मुंह से बदबू नहीं आती। लेकिन जब आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो यह बैड बैक्टीरिया विकसित होने लगते हैं और आपके मुंह से दुर्गंध आती है।

खाने का रखें ख्याल

आप जो कुछ भी खाते हैं, उसका प्रभाव भी आपकी सांसों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप प्याज, लहसुन, अत्यधिक अम्लीय या फ्रक्टोज युक्त शुगर का सेवन करने से बाद में आपके मुंह से स्मेल आती है। इसलिए आप ऐसे भोजन को खाने के बाद ब्रश अवश्य करें, ताकि आपके मुंह के बदबू न आए।

सेब का कमाल

आपको शायद जानकर हैरानी हो लेकिन सिर्फ सेब की मदद से भी मुंह से आने वाली बदबू को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप हर रोज सेब को चबा-चबाकर खाएं। इससे निकलने वाला रस आपके मुंह में लार को बढ़ावा देता है, जिसके कारण आपके मुंह से बदबू नहीं आती। इसके अतिरिक्त रोजाना एक सेब का सेवन करने से आपके पीले दांतों की समस्या भी दूर होती है।

इस्तेमाल करें सरसों का तेल

अगर आप अपने मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चुटकी भर नमक में 1 बूंद सरसों के तेल की डाल लें और इससे दांतों और मसूढ़ों का मालिश करें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यह मुंह की दुर्गंध को दूर करने के साथ-साथ दांतों की अन्य समस्याओं जैसे दांत दर्द व पीलेपन को भी दूर करता है।

छोटे उद्यमों की ऋण गारंटी योजना की संसदीय समिति ने की समीक्षा

उद्यमों को बैंक ऋण दिलाने के लिए बुलाई जाएगी विशेष बैठक- मुख्य सचिव



जयपुर (कासं)। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राजस्थान के अध्ययन दौरे के दौरान शुक्रवार को जयपुर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा की। राज्यसभा सांसद एवं समिति अध्यक्ष तिरुची शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए। तिरुची शिवा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं। समिति ने बैंकों और उद्योग संघों के साथ चर्चा की कि ऋण गारंटी योजना का लाभ उद्यमियों तक कैसे पहुंच रहा है और ऋण लेने में उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन उद्यमों से खरीद के अनिवार्य लक्ष्यों, खरीद अनुबंधों और बकाया राशि के समय पर भुगतान पर भी बात हुई। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्यमों के विकास और ऋण गारंटी योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजस्थान में इन उद्यमों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रदेश में करीब 31 लाख पंजीकृत एमएसएमई हैं, जिनसे करीब 92 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें करीब 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं। श्रीनिवास ने कहा कि पहली बार कारोबार शुरु करने वाले लोगों के लिए बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण मिलना महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) 10 करोड़ रुपये तक के पात्र ऋणों पर बैंकों को गारंटी देता है। राज्य की योजनाओं में पात्र उद्यमियों के लिए ब्याज में छूट, कारोबार शुरू करने के लिए अपनी ओर से लगाई जाने वाली राशि में सहायता या ऋण गारंटी शुल्क की भरपाई का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने कहा कि समिति के निर्देशों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इसमें उद्यमों को बैंक ऋण मिलने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा कर सुझाव तैयार किए जाएंगे। बैंकों को मिले ऋण आवेदनों और मंजूर किए गए आवेदनों के बीच अंतर की समीक्षा होगी। जिन परियोजनाओं के लिए ऋण मांगा गया है, उनके व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं को दोबारा परखा जाएगा। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज निवेश पोर्टल को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि निवेश आवेदनों पर समुचित कार्रवाई हो सके। श्रीनिवास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सभी बैठकों में भाग लिया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं पर अलग से भी बैठकें हुई।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई योजनाओं पर केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से आगे भी चर्चा होगी। उन्होंने मुद्रा योजना के तर्ज पर हर तीन महीने में राज्यों में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का सुझाव दिया।

बैठक में समिति के सदस्य, रेल मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और राजस्थान सरकार के अधिकारी तथा बैंकों और उदयोग संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना

14 नवंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा 16 नवंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए होगा मतदान



जयपुर (कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों में 14 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के उपरांत ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई। मतदान दलों की रवानगी के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति एवं सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी के मतदान दल निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार रवाना हुए। पंचायत समिति क्षेत्र बस्सी के 145, तूंगा के 74, जमवारामगढ़ के 129 तथा आंधी के 98 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए। इस प्रकार चतुर्थ चरण में कुल 446 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल अपने निर्धारित गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हुए।

उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बस्सी की 42, तूंगा की 24, जमवारामगढ़ की 42 तथा आंधी की 32 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। इस प्रकार चारों पंचायत समितियों की कुल 140 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। चतुर्थ चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शनिवार, 14 नवंबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद रविवार, 15 नवंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। सोमवार, 16 नवंबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी तथा मंगलवार, 17 नवंबर को उपसरपंच पद के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा मतदान के उपरांत ईवीएम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित रूप से संग्रहण स्थल तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं।

अजमेर में बांग्लादेशी नागरिकों पर शिकंजा, पांच सदस्यीय परिवार दस्तयाब



जयपुर (कासं)। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं निष्कासन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 28वीं कार्रवाई करते हुए पांच सदस्यीय एक परिवार को दस्तयाब किया है। इनमें बांग्लादेशी मूल के 63 वर्षीय माजिद अली, उसकी 55 वर्षीय पत्नी फरजान खान तथा उनके दो पुत्र और एक पुत्री शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ अजमेर जिले में अब तक दस्तयाब किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 66 हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज डॉ. रवि के निर्देशानुसार अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों एवं अन्य घुसपैठियों की पहचान कर उनके निष्कासन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ के मार्गदर्शन तथा वृत्ताधिकारी दरगाह हर्षित शर्मा के नेतृत्व में सीआईडी जोन अजमेर के साथ विशेष टीम गठित की गई है। अभियान के तहत गठित टीम ने मुखबिरों से आसूचना संकलन, तकनीकी साधनों और विभिन्न जानकारियों के आधार पर दरगाह क्षेत्र के संभावित ठिकानों पर सघन तलाश की। टीम ने दरगाह बाजार, जालियान कब्रिस्तान, अंदरकोट, नई सड़क, तारागढ़ की पहाड़ी, सिलावट मोहल्ला, बड़े पीर का चिल्ला, लंगर खाना गली, चश्मा-ए-नूर तारागढ़, त्रिपोलिया गेट, सोहले खम्भा, झालरा और लाखन कोटड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में जांच की। इस दौरान एक परिवार को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में परिवार के मुखिया ने अपना नाम माजिद अली पुत्र उनाब अली उम्र 63 वर्ष मूल निवासी जोहरी मोहल्ला मोहम्मदपु जिला ढाका बांग्लादेश बताया। उसके साथ पत्नी फरजान खान उम्र 55 वर्ष तथा उनके तीन बच्चे भी मिले। प्रारंभिक पूछताछ में माजिद अली ने बताया कि वर्ष 2006 में उसका निकाह बांग्लादेश निवासी फरजान खान से हुआ था। वर्ष 2007 में वह अपनी पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल के हिली बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ। इसके बाद दोनों ट्रेन से दिल्ली पहुंचे और करीब दो वर्ष तक वहां खानाबदोश के रूप में जीवनयापन किया। वर्ष 2009-10 में वे अजमेर दरगाह शरीफ क्षेत्र में आए और यहीं रहने लगे। माजिद अली ने बताया कि उसके दो पुत्र और एक पुत्री हैं। शुक्रवार 13 नवंबर को दरगाह थाना पुलिस एवं सीआईडी जोन अजमेर की टीम ने परिवार को दस्तयाब कर पुलिस थाना दरगाह लाकर पूछताछ की।

ज्वैलरी खरीदने के बहाने 1510 ग्राम सोना ठगा, तीन आरोपी गिरफ्तार



जयपुर (कासं)। किशनगढ़ में ज्वैलरी खरीदने के बहाने व्यापारी को धोखा देकर करीब 1510 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हुए तीन शातिर आरोपियों को मदनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये कीमत के सोने के विभिन्न आभूषण तथा 1 लाख 32 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर लगातार पीछा करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों, लूट, चोरी और नकबजनी के मामलों में फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. लाल चंद कायल तथा वृत्ताधिकारी किशनगढ़ शहर धर्मराज चौधरी के निर्देशन में थानाधिकारी मदनगंज भवानी सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।

घटना के संबंध में परिवादी मनफूल सोनी निवासी चाड़वास जिला चुरु ने 10 नवंबर 2026 को थाना मदनगंज में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवादी ने बताया कि वह चाड़वास स्थित पायल ज्वैलर्स का प्रोपराइटर है। उसके मोबाइल पर किशनगढ़ निवासी राहुल सोनी नामक व्यक्ति पिछले तीन-चार दिनों से फोन कर उसकी फर्म से ज्वैलरी खरीदने का ऑर्डर दे रहा था। उसके विश्वास में आकर परिवादी ने 5 नवंबर 2026 को अपने स्टाफ के कर्मचारी राम सोनी और मनोज सोनी को करीब 1510 ग्राम वजन के सोने के आभूषण बिल सहित राहुल सोनी के पास किशनगढ़ भेजा। दोनों कर्मचारी दोपहर करीब 3:30 बजे किशनगढ़ पहुंचे। राहुल सोनी उन्हें गुणसागर ज्वैलर्स के ऊपर स्थित मकान में ले गया, जहां कर्मचारियों ने उसे आभूषण दिखाकर बिल सौंप दिया। राहुल ने माल का चयन करवाने का बहाना बनाया और वहां से चला गया। कर्मचारियों द्वारा कई बार फोन करने पर वह वापस आया और भुगतान तथा शेष सामान देने के बहाने उन्हें आरआर ज्वैलर्स, मदनगंज ले गया।

9.19 लाख के भुगतान चेक पर हस्ताक्षर करने की एवज में मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने झालावाड़ में रंगे हाथों पकड़ा



जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी झालावाड़ द्वारा कार्यवाही करते हुए मस्तराम मीणा, निरीक्षक, सहकारी समितियां, झालावाड़, हाल अतिरिक्त कार्यभार महाप्रबंधक, झालावाड़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड, झालावाड़ को परिवादी से 15,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी झालावाड़ पर 12.11.2026 को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी फर्म गुरुकृपा मेडीकोज, झालरापाटन द्वारा झालावाड़ सहकारी उपभोक्ता भण्डार में दवाईयों की सप्लाई की गई थी, जिसके लगभग 15.32 लाख रुपये बकाया थे। उक्त बकाया भुगतान में से 9.19 लाख रुपये के चैक पर हस्ताक्षर करने की एवज में महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरोपी मस्तराम मीणा द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। उक्त शिकायत पर दिनांक 12.11.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से बकाया भुगतान की राशि के 10 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करना सत्यापित हुआ।

बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा 5.00 लाख रुपये के चैक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही शेष 4.19 लाख रुपये का चैक एक-दो दिन में जारी करने का आश्वासन दिया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि की मांग के अनुरूप परिवादी से 25,000 रुपये अगले दिन देने तथा शेष राशि चैक पास होने के बाद देने पर सहमति व्यक्त की गई। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 5.00 लाख रुपये के चैक पर हस्ताक्षर कर संबंधित बैंक के नाम पत्र सहित परिवादी को सौंप दिया गया। 13.11.2026 को परिवादी द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था किए जाने पर एसीबी द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित की गई। एसीबी कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी चौकी झालावाड़ के पुलिस निरीक्षक साजिद खान के नेतृत्व में टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी मस्तराम मीणा को परिवादी से 15,000 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमाला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध एसीबी में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिले तो प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं उपलब्ध तथ्यों की जानकारी हेतु एसीबी की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औपचारिक रूप से सीधे सम्पर्क कर अपना पक्ष / स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। एसीबी द्वारा दोषसिद्ध होने से पूर्व तथ्यों एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण कर नियमानुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है। एसीबी के नाम पर किसी के भय या दबाव में आकर धोखाधड़ी का शिकार ना बनें।

प्रशिक्षण स्थल से मतदान दल को बिना सूचना नदारद हुए सहायक मतदान अधिकारी निलंबित, 18 अन्य कार्मिकों को नोटिस

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

जयपुर (कासं)। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के अंतर्गत जिले की चार पंचायत समितियों (जमवारामगढ़, आंधी, बस्सी एवं तूंगा) में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण स्थल भवानी निकेतन के फार्मेसी कॉलेज परिसर से संबंधित पंचायत मुख्यालयों पर स्थित मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जयपुर संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति आंधी के मतदान दल में सहायक मतदान अधिकारी-प्रथम के पद पर नियुक्त एक कार्मिक हस्ताक्षर करने के बाद मतदान दल के टेंट से बिना किसी सूचना के फोन बंद कर नदारद हो गया। टेंट में नियुक्त अधिकारियों द्वारा माइक पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद उक्त कार्मिक उपस्थित नहीं हुआ। इस पर संबंधित कार्मिक को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अनुपस्थित 18 अन्य कार्मिकों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसे राजकीय महत्व के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की सूची तैयार की जा रही है।

न्यूज इनबॉक्स

कांग्रेस ने बूथ स्तर पर लॉन्च किया 'वोट रक्षक ऐप', संगठन को मजबूत करने पर जोर

जयपुर (कासं)। एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को इंचार्ज स्टेट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए 'वोट रक्षक ऐप' लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल ने सभी पदाधिकारियों को वोट रक्षक ऐप की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ऐप के माध्यम से बूथ स्तर पर कार्यों को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। बैठक में ऐप को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और संगठन के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

इंतजारशास्त्र के बाद अब 'बजट फाइल्स' : भाजपा सरकार के वादों और दावों की खुलेगी पोल

जयपुर (कासं)। 'इंतजारशास्त्र' के बाद अब एक नई वीडियो सीरीज़ 'बजट फाइल्स' शुरू हो रही है। इसमें राजस्थान की भाजपा सरकार की बजट घोषणाओं और उनकी डिलीवरी की हकीकत जनता के सामने रखी जाएगी। सीरीज़ 14 नवंबर 2026 से हर शनिवार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी होगी। भाजपा सरकार अब तक चार बजट दस्तावेज़ पेश कर चुकी है: लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और बजट 2026-27। इनमें सड़कों, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी बड़ी संख्या में घोषणाएं की गईं। 'बजट फाइल्स' हर शनिवार इनमें से एक बड़ी घोषणा को उठाएगी और पूछेगी कि घोषणा तो हुई, पर उसके क्रियान्वयन की हकीकत क्या है। बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, जनता से किया गया वादा होता है। 'बजट फाइल्स' का मक़सद इन वादों का हिसाब जनता तक पहुंचाना और सरकार से जवाबदेही मांगना है, ताकि घोषणाएं कागज़ों तक सीमित न रह जाएं। इस सीरीज का पहला एपिसोड 14 नवंबर को प्रसारित होगा।

पंचायत चुनाव के मतदान पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जयपुर (कासं)। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच-सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए निर्धारित मतदान तिथियों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शनिवार, 14 नवंबर को तथा पंच-सरपंच पदों के लिए सोमवार, 16 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत भी मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन क्षेत्रों के मतदाता अपने6 मताधिकार का उपयोग कर सकें। पुनर्मतदान की स्थिति में भी जिन मतदान क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहां पुनर्मतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कार्मिकों, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पंचायतीराज निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमानुसार मतदान तिथियों का सवैतनिक अवकाश देय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं नियोजकों से आदेशों की पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

जयपुर में हरमनप्रीत के वैक्स स्टैच्यू का अनावरण, दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनीं

जयपुर (कासं)। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में शुक्रवार को महिला क्रिकेट जगत की सितारा खिलाड़ी और भारत वुमन क्रिकेट की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टैच्यू का भव्य अनावरण हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथों से किया। जैसे ही पर्दा हटा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह वैक्स स्टैच्यू अब स्थायी रूप से हिस्टोरिका - स्टेप इनटू हिस्ट्री, नाहरगढ़ फोर्ट (पूर्व में जयपुर वैक्स म्यूजियम) में लगाया जाएगा, जहां पर्यटक इसे देख सकेंगे। हरमनप्रीत कौर दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं, जिनका वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है। हिस्टोरिका के फाउंडर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम की टीम ने इसके लिए पहले हरमन के पास जाकर उनका विस्तृत माप, फोटो और वीडियो लिए थे, ताकि उनका जीवंत, लाइफ-साइज वैक्स रूप तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान जयपुर क्रिकेट के नन्हे-मुन्ने और युवा क्रिकेट खिलाड़ियों बल्ला उठाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसे देखकर हरमनप्रीत भावुक हो गईं। उन्होंने बच्चों से बात की, उनके साथ फोटो खिंचवाई और उन्हें मेहनत और सपनों पर भरोसा रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में हरमनप्रीत कौर के जीवन पर एक भावनात्मक फिल्म भी दिखाई गई जिसमें मोगा के छोटे से शहर से लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी तक, संघर्ष, मेहनत और 2025 में भारत को पहला महिला वनडे विश्व कप जिताने तक की कहानी को दर्शाया गया। हरमनप्रीत ने 2025 में भारतीय टीम को पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब दिलाया था। इसी ऐतिहासिक जीत को इस वैक्स स्टैच्यू के माध्यम से हमेशा के लिए अमर किया गया है।

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (S/ P), JHOTWARA ROAD, JAIPUR

Tender Inviting Bid

TENDER VALUE ABOVE TEN LAKH AND UP TO ONE CRORE

NIT - 11 - Bid for the purchase of CW Printing Paper and Aluminium Coil are invited from interested bidder up to (Time) 18.00 PM date 01.12.2026 other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.raj.nic.in** of the state; and **https://transport.rajasthan.gov.in.**

Closing Date: - 01.12.2026, Opening date:- 02.12.2026

UBN No. : RTC2627GLRC00629, RTC2627GLRC00630

राज.संवाद/सी/26/13164 विज्ञापन संख्या 285/2026-27 General Manager (S/P)

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, **Email:-** lokjeewanjpr@gmail.com **भीलवाड़ा कार्यालयः** 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। **फोनः** 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, **मो.** 8306792625